



Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 14 फरवरी, 2023

वशिव रेडियो दविस

भारत के प्रधानमंत्री ने 'वशिव रेडियो दविस' पर रेडियो श्रोताओं और प्रसारण माध्यम से जुड़े अन्य लोगों को बधाई दी। यह प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम "रेडियो एंड पीस" है। 3 नवंबर, 2011 को [यूनेस्को](#) के 36वें सत्र ने 13 फरवरी को वशिव रेडियो दविस मनाने की घोषणा की, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र द्वारा 13 फरवरी, 1946 को संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की गई थी। इस दिन को वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतरराष्ट्रीय दविस के रूप में अपनाया गया था। रेडियो के महत्त्व के बारे में जनता और मीडिया के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा रेडियो के माध्यम से सूचना तक पहुँच को प्रोत्साहित करने के लिये प्रत्येक वर्ष यह दिन मनाया जाता है। भारत में लगभग 479 रेडियो स्टेशन हैं जो ऑल इंडिया रेडियो को दुनिया के सबसे बड़े प्रसारकों में से एक बनाते हैं। यह लगभग 99.19% भारतीय आबादी को कवर करता है।

और पढ़ें... [सामुदायिक रेडियो](#)

"खनन प्रहरी" मोबाइल एप

भारत सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिये "खनन प्रहरी" नामक एक मोबाइल एप और एक वेब एप कोयला खदान नगिरानी और प्रबंधन प्रणाली (Coal Mine Surveillance and Management System- CMSMS) लॉन्च की है। यह मोबाइल एप कोयला मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है जो नागरिकों को घटना के स्थान से भू-टैग की गई तस्वीरों तथा टेक्स्ट के रूप में सूचना का उपयोग करके अवैध कोयला खनन की घटनाओं के बारे में रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। इस संबंध में किये गए वैधानिक उपायों में शामिल हैं- कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973; खनन रियायत नयिम, 1960; कोलियरी नयित्रण नयिम, 2004' खान और खनन (विकास एवं वनियमन) अधिनियम, 1957। इसके अलावा इन क्षेत्रों तक पहुँच और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिये परतियक्त खदानों के मुहाने पर कंक्रीट की दीवारें नरिमति की गई हैं। साथ ही मौजूदा सुरक्षा/CISF कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और अवैध खनन के वभिनिन पहलुओं की नगिरानी के लिये CIL (Coal India Ltd.) की कुछ सहायक कंपनियों में वभिनिन सत्रों पर समतियों/कार्यबलों का गठन किया गया है।

और पढ़ें... [भारत में कोयला क्षेत्र](#)

APEDA ने अपनी यात्रा के 37 साल पूरे किये

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद नरियात विकास प्राधिकरण (APEDA), जसिवर्ष 1986 में संसद के एक अधनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था, वाणजिय और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करता है। कृषि जसियों के नरियात को बढ़ावा देने हेतु APEDA को अधिकार प्राप्त है। इसके अतरिकित APEDA को चीनी के आयात की नगिरानी करने की जमिमेदारी भी सौंपी गई है। 'वोकल फॉर लोकल' तथा 'आत्मनरिभर भारत' के वचिारों के अनुरूप APEDA स्थानीय रूप से प्राप्त [जीआई \(भौगोलिक संकेत\)](#) के साथ-साथ स्वदेशी, जातीय कृषि उत्पादों के नरियात को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वशिव व्यापार संगठन व्यापार डेटा के आधार पर भारत वतित वर्ष 2021-22 में 24.77 बलियिन अमेरिकी डॉलर के नरियात के साथ कृषि उत्पादों का वशिव का आठवाँ सबसे बड़ा नरियातक बन गया है। APEDA की हाल की कुछ पहलों में फार्मर कनेक्ट पोर्टल, वाराणसी कृषि-नरियात हब (VAEH); बाजरा आदि के प्रचार के लिये बाजरा पोर्टल सम्मलित है।

और पढ़ें... [APEDA](#)

नरिमाण से शक्ति पहल

कर्मचारी राज्य बीमा नगिम (ESIC) ने बुनयिदी ढाँचे के आधुनिकीकरण के लिये 'नरिमाण से शक्ति' नामक एक पहल की शुरुआत की है। 'नरिमाण से शक्ति' पहल में चरणबद्ध तरीके से ईएसआई योजना अस्पतालों और औषधालयों का उन्नयन/आधुनिकीकरण, बेहतर आधुनिक सुवधियों के साथ 100/200/500 बेड वाले अस्पतालों के लिये मानक डिज़ाइन तैयार करना, पर्यवेक्षण, नरिमाण की गुणवत्ता सुनश्चित करने के लिये नई भवन प्रौद्योगिकियों को अपनाने के साथ-साथ भूमि/संपत्ति दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, परयोजना की नगिरानी हेतु ऑनलाइन रीयल-टाइम डैशबोर्ड आदि शामिल हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधनियम, 1948 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIC), एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है जो इस योजना के तहत शामिल शर्मिक आबादी और उनके आश्रितों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये तैयार की गई है।

और पढ़ें... [ESIC](#)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-14-february-2023>

